



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1265]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 2017/वैशाख 15, 1939

No. 1265]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 2017/VAISAKHA 15, 1939

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 मई, 2017

का.आ. 1433(अ).—सुरक्षा उपाबंध ने अपनी 317वीं बैठक में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत संकल्प 827 (1993) अंगीकृत किया [उपाबंध I के रूप में इस आदेश के साथ संलग्न], जिसके द्वारा पूर्व यूगोस्लाविया राष्ट्र के राज्यदलों में किये गये अंतरराष्ट्रीय मानवीय विधि के गंभीर उल्लंघनों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन चलाने के एकमात्र प्रयोजन के लिए अंतरराष्ट्रीय अधिकरण की स्थापना की गई;

और, इसी संकल्प में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी राष्ट्र संकल्प 827 (1993) और अंतरराष्ट्रीय अधिकरण की कानून [अनुबंध II के रूप में इस आदेश के साथ संलग्न] के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अधिकरण और उसके अंगों के साथ पूरी तरह से सहयोग करेंगे;- और उसके फलस्वरूप सभी राष्ट्र सहायता के लिए अनुरोधों अथवा कानून के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत विचारण चैम्बर द्वारा जारी किये गए आदेशों के अनुपालन में राष्ट्रों की बाध्यता सहित मौजूदा संकल्प और कानून के उपाबंधों के कार्यान्वयन के लिए अपने देशी विधि के अंतर्गत आवश्यक उपाय करेंगे;

और, 1991 से, पूर्व यूगोस्लाविया राज्य के राज्यक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानवीय विधि के गंभीर उल्लंघनों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ विचारण के लिए अंतरराष्ट्रीय अधिकरण के विचारण चैम्बर I ने तारीख 5 अक्टूबर, 2016 को एक पक्षीय आदेश पारित किया और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों को भेजा जिसमें अधिकरण के अवमान और साक्ष्यों के साथ व्यवधान करने के लिए पीटर जोजिक, जोवोओस्टोजिक और विजेरिका राडेता पर भेजा लगाया गया था;

और, अंतरराष्ट्रीय अधिकरण के अभियोजन चैम्बर I ने तारीख 5 अक्टूबर, 2016 को एक पक्षीय आदेश पारित किया और उपर्युक्त तीनों व्यक्तियों नामतः पीटर जोजिक, जोवोओस्टोजिक और विजेरिका राडेता की गिरफ्तारी, बंदी सुनिश्चित करने और उन्हें अधिकरण को हस्तांतरित करने के लिए सभी यथोचित कर्मिष्ठता के साथ मुस्तैदी से कार्य करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों के सभी प्राधिकरणों, अधिकारियों और अभिकर्ताओं को भेजा;

अतः, अब केंद्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम 1947 (1947 का 43) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सुरक्षा परिषद संकल्प 827 (1993) के अनुपालन में निम्नलिखित आदेश देती है कि भारत की विधि प्रवर्तन एजेंसियां;

- (i) निम्नलिखित व्यक्तियों की गिरफ्तारी, बंदी सुनिश्चित करने के लिए शीघ्रता से कार्य करेंगी और, पूर्व यूगोस्लाविया के लिए अंतरराष्ट्रीय दांडिक अधिकरण (आईसीटीवाई), अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, शांति पैलेस कार्नेगीप्लेन 2, 2517 केजी दि हेग, दि नीदरलैण्ड्स को हस्तांतरित करेंगी

[फा. सं. यू.-II/152/23/2010]

रुद्रेन्द्र टंडन, संयुक्त सचिव (यूएनपी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 5th May, 2017

S.O. 1433(E).—Whereas, the Security Council at its 317th Meeting adopted resolution 827(1993) [appended to this Order as Annexure I], under Chapter VII of the Charter of the United Nations which established an International Tribunal for the sole purpose of prosecuting persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former state of Yugoslavia;

And whereas, the same resolution also decided that all states shall cooperate fully with the International Tribunal and its organs in accordance with the resolution **827(1993)** and the Statute of the International Tribunal [appended to this Order as Annexure II],;—and that consequently all States shall take measures necessary under their domestic law to implement the provisions of the present resolution and the Statute, including the obligation of States to comply with requests for assistance or orders issued by a Trial Chamber under Article 29 of the Statute;

And whereas, the Trial Chamber I of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law in the Territory of the former state of Yugoslavia since 1991 (The Tribunal) passed an *ex parte* order dated the 5th October, 2016 and sent to all United Nations member states, indicting Petar Jojic, Jovo Ostojic and Vjerica Radeta for contempt of the Tribunal and interfering with witnesses;

And whereas, the Trial Chamber I of the International Tribunal passed an *ex parte* order dated the 5th October, 2016 and sent to all authorities, officers and all agents of United Nations member states, to act promptly with all due diligence to secure the arrest, detention, and transfer to the Tribunal of the aforesaid three persons namely Peter Jojic, Jovo Ostojic and Vjerica Radeta;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947) and complying with the Security Council Resolution 827(1993), the Central Government hereby makes the following order that the law enforcement agencies of India shall;

- (i) act promptly to secure the arrest, detention of the following persons and transfer to the Registrar, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), International Court of Justice, Peace Palace, Carnegieplein 2, 2517 KJ The Hague, The Netherlands

[F. No. U.-II/152/23/2010]

RUDRENDRA TANDON, Jt. Secy. (UNP)